एनसीईएल का निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य तय

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 02 – मई 2025

पीएम अन्न भंडारण योजना

पैक्स बनाएंगे हर ग्राम पंचायत में गोदाम

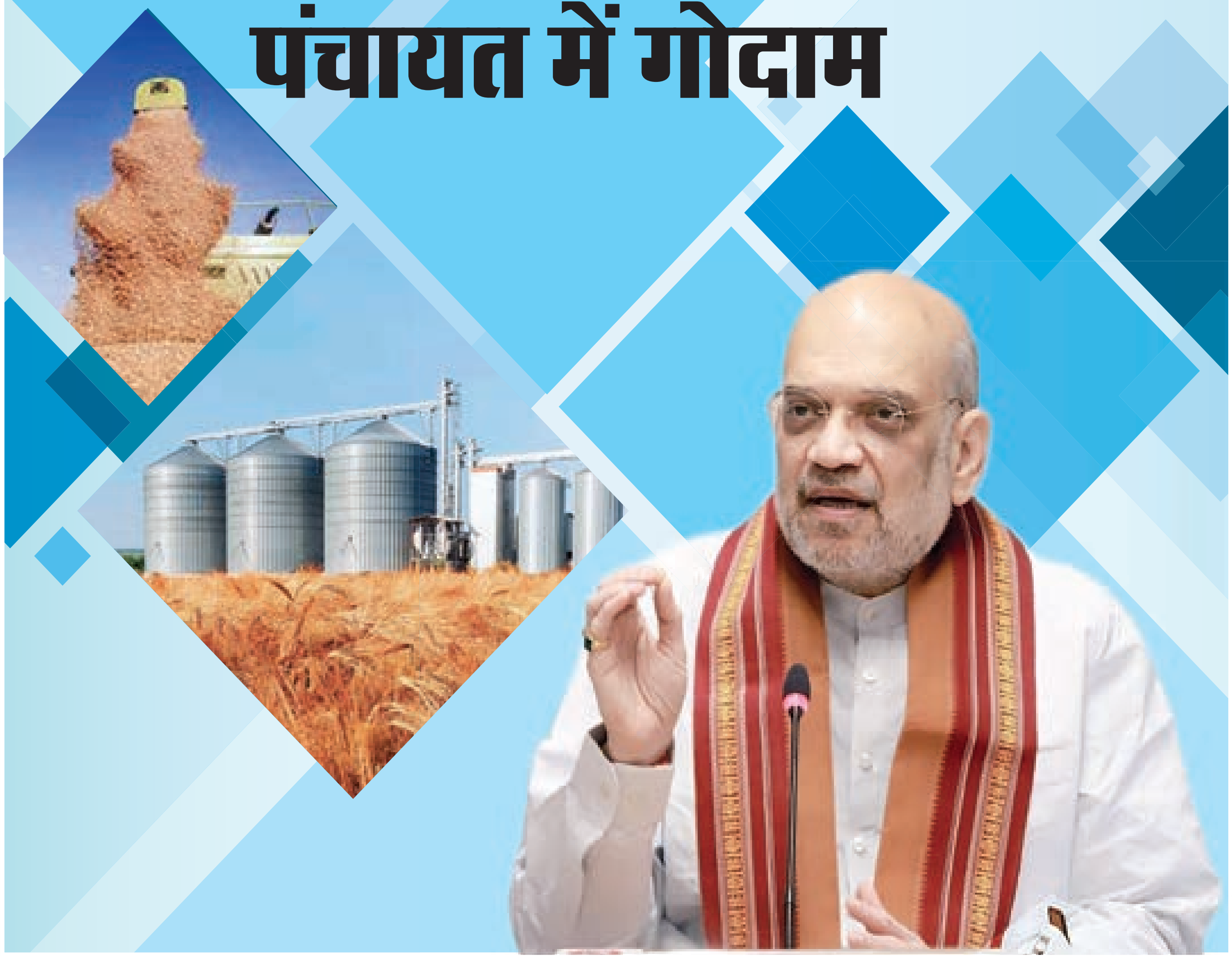

बोडोफा की प्रतिमा देशभर के जनजातीय समाज के आत्मसम्मान का प्रतीक

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
मई 2025, अंक 02, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा
समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली: 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:

Ministry of Cooperation

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुन: उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़े प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

05

आवरण कथा

पैक्स बनाएंगे हर ग्राम पंचायत में गोदाम

विश्व की सबसे बड़ी आबादी की पुख्ता खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जहां खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्पादकता पर जोर दे रही है, वहीं उपज के सुरक्षित भंडारण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

12

एनसीईएल का निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य तय

भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए निर्यात में भी इन समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है।

अब भारत के भीतर ही रहेगा सीमा पार बह रहा पानी — 14

वायब्रेंट गुजरात और मैग्नीफिसेंट महाराष्ट्र देश के विकास के मजबूत स्तंभ — 16

'वसुधैव कुटुंबकम' के प्राचीन दर्शन में निहित है भारत का अंतरिक्ष विजन — 18

स्वस्थ शरीर का गेटवे है स्वस्थ लिवर — 20

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 10 साल में मिली नई गति — 22

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सहकारी समितियों में बढ़ेगी पारदर्शिता — 28

29

जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे रहा एनसीओएल

समुचित खाद्यान्न भंडारण पर फोकस

देश की खाद्य सुरक्षा में खाद्यान्न भंडारण के महत्व को देखते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय गोदामों के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी के मद्देनजर सहकारिता मंत्रालय ने विश्व की सबसे बड़ी पीएम अन्न भंडारण योजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे फसलों की पोस्टहार्वेस्टिंग में होने वाली क्षति को रोकने और भंडारण के अभाव में होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की लागत एक लाख करोड़ रुपए है। जबकि इससे देश में अतिरिक्त सात करोड़ टन अनाज भंडारण क्षमता विकसित होगी। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 33.02 करोड़ टन के मुकाबले केवल 47 प्रतिशत अनाज के लिए ही गोदाम उपलब्ध है। भंडारण क्षमता में विकास करने की पर्याप्त संभावना है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशानिर्देशन में नये गोदामों का निर्माण शुरू हो चुका है। परंपरागत भंडारण से भी अनाज का नुकसान होता है। इस बाबत आधुनिक भंडारण की सुविधा की आवश्यकता है। देश में इस समय 14 करोड़ टन अनाज के भंडारण के लिए गोदाम उपलब्ध हैं। सहकारिता मंत्रालय की योजना के क्रियान्वयन से भंडारण क्षमता बढ़ाकर 21 करोड़ टन करने की है।

पोस्टहार्वेस्टिंग में फसलों की होने वाली की क्षति को रोकने से खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर अमल के तहत देश की दो तिहाई आबादी को मुफ्त अनाज वितरण किया जाता है, जिसके लिए वार्षिक 6.02 करोड़ टन अनाज की आवश्कता पड़ती है। दूसरा, देश में आपदा काल के लिए खाद्यान्न के बफर स्टॉक की जरूरत होती है। खाद्यान्न के भंडारण के लिए पर्याप्त गोदामों की जरूरत है, जिसके लिए पीएम अन्न भंडारण योजना मुफीद साबित होगी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और पैदावार के समुचित भंडारण के साथ रखरखाव सुनिश्चित करने में यह योजना मुफीद साबित होगी। केंद्र की मोदी सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

भारत की दो तिहाई गरीबों के लिए मुफ्त अनाज वितरण के लिए तकरीबन छह करोड़ टन से अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा देश की खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीतिक भंडारण की भी जरूरत है, जिसके लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। पूरे देश में खाद्यान्न वितरण की विस्तृत नेटवर्किंग करने और वहां तक अनाज पहुंचाना हमेशा एक चुनौती रहा है। इसीलिए सहकारिता क्षेत्र ने अपनी प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से छोटे-छोटे गोदाम बनाने का फैसला किया है। स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले अनाजों का भंडारण वहीं किया जाएगा ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनाज का वितरण भी आसानी से किया जा सकेगा। इससे अनाज की सरकारी खरीद, ढुलाई और फिर वितरण में लॉजिस्टिक की लागत में भारी कमी आएगी, जिससे राजस्व के अपव्यय को रोकने मे मदद मिलेगी।

पीएम अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इसके पहले चरण का शुभारंभ हो चुका है। सहकारिता की सबसे निचली इकाई प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ग्राम पंचायत स्तर पर गोदामों का निर्माण करने में जुट गई है। भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना पर अमल से गोदामों के निर्माण शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बागवानी (फल, फूल और सब्जियां) उपज के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी, जिससे पूरे देश में सभी खाद्य वस्तुओं की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

जय सहकार

विकसित भारत की यात्रा में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि यह हमारे सामर्थ्य को भी बढ़ाती है। 'विकास भी-विरासत भी' के मंत्र के साथ नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

दुर्गम सीमाओं और विषम मौसमीय परिस्थितियों में भी सीमाओं पर मुस्तैद बीएसएफ ने 1971 के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिन्दूर तक सीमा सुरक्षा के अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाया है। मोदी सरकार बीएसएफ को अत्याधुनिक तकनीकों और संसाधनों से सुसज्जित कर इसे विश्व का सबसे सशक्त सुरक्षा बल बना रही है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और सुशासन के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पूर्ण किया है। इसमें समाज के चार वर्गों - गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति ने विकास एवं सफलता की एक नई कहानी लिखी है।

श्री कृष्ण पाल गूजर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

सहकारी वस्तु एवं आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से देश में सहकारी आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है। किसी भी क्षेत्र की सफलता और समृद्धि के लिए पहले उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं का वित्तीय सशक्तिकरण किया गया है। इस पहल से किसानों और ग्रामीण उद्यमों को लाभ मिलने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी नई गति और मजबूती मिली है।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

पीएम अन्न भंडारण योजना

पैक्स बनाएंगे हर ग्राम पंचायत में गोदाम

सहकार जागरण टीम

- पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों में गोदाम तैयार, अनाज भंडारण भी शुरू
- देश के कोने-कोने में पैक्स के माध्यम से गोदाम बनाने की तैयारी
- विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर आएगी एक लाख करोड़ रुपये की लागत

विश्व की सबसे बड़ी आबादी की पुख्ता खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जहां खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्पादकता पर जोर दे रही है, वहीं उपज के सुरक्षित भंडारण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना की शुरूआत की गई है। इसके तहत पैक्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में अनाज के गोदाम बनाए जा रहे हैं। इस योजना से न सिर्फ गांवों में ही अनाज भंडारण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि उपज की पोस्टहार्वेस्टिंग में होने वाले भारी नुकसान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। भंडारण के अभाव में होने वाली क्षति को भी रोका जा सकेगा।

गांव में गोदाम बनेगा तो उनका रखरखाव, प्रबंधन करने जैसे प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा अनाजों की ढुलाई सहित अन्य अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे जो निश्चित तौर पर उस गांव और पंचायत के युवाओं के लिए ही उपलब्ध होंगे जहां यह बनेगा। इसके साथ ही कृषि और उससे संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी निर्माण होगा जिसमें भी रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पांच वर्ष में कुल सात करोड़ टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इसमें सबसे अहम भूमिका सहकारी क्षेत्र की निचली इकाई पैक्स की है। पैक्स को कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने, किसानों से अनाज की खरीद करने, मंडियों से अनाज खरीद के बाद उसकी प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने और खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता विकसित करने के लिए नामित किया गया है। योजना को देश भर में लागू करने के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुल 24 राज्यों के 24 जिलों

की कुल 24 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का चयन किया गया है। इनमें से 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण कर उनमें भंडारण शुरू किया जा चुका है। इनका निर्माण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) के सहयोग से किया गया है। इन 11 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान के 11 पैक्स शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर कुल 9,750 टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया है।

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से उत्साहित होकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने विस्तारित पायलट के तहत भाग लेने के लिए 575 अतिरिक्त पैक्स की पहचान की है। इनमें से 500 पैक्स में गोदाम के निर्माण के लिए शिलान्यास किया जा चुका है। 326 पैक्स के डीपीआर प्रस्तुत किए गए हैं और 136 पैक्स का वित्तीय समापन पूरा हो चुका है। इन गोदामों की क्षमता उपयोग के लिए एफसीआई, एनसीडीसी और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) हो चुका है।

अनुमान है कि वर्ष 2047 तक भारत की आबादी लगभग 1.61 अरब हो जाएगी जिसके लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्न भंडारण के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी। यह परियोजना जमीनी स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देगी। यह पैक्स को भी मजबूत करेगा, फार्मगेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा और किसानों की आय बढ़ाएगा। समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जिससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।

सभी ब्लॉकों में बनेंगे गोदाम

ग्रामीण गोदामों के निर्माण के पहले चरण में देश के सभी ब्लॉकों में गोदाम बनाए जाएंगे। इस हिसाब से तकरीबन 50,000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण पहले चरण में होने का अनुमान है इस योजना में नई फ्लेक्सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज की जरूरत के हिसाब से 50 टन, 100 टन, 250 टन, 500 टन और 750 टन क्षमता के साइलोज (आधुनिक तकनीक से स्टील के गोदाम) और सामान्य गोदाम बनाए जा रहे हैं। पैक्स के बनाए इन गोदामों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य प्राइवेट एजेंसियों को भंडारण के लिए किराये पर दिया जाएगा। इससे पैक्स की आमदनी बढ़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पैक्स के खरीदे अनाज की बिक्री की जा सकेगी। इन गोदामों में अनाज की प्रोसेसिंग की भी सुविधा होगी, जिससे उपज को मूल्यवर्धित करके बेचा जा सकेगा।

ग्राम स्तर पर बनाए जाने वाले छोटे गोदामों से किसानों को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाने का खर्च भी कम होगा। अभी होता यह है कि गांव से अनाज शहर के गोदामों तक

> दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की प्रायोगिक परियोजना के परिणामस्वरूप, पैक्स स्तर पर कुल 9,750 मीट्रिक टन विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाई गई है। पैक्स स्तर पर गोदामों के निर्माण का उद्देश्य पर्याप्त विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाकर खाद्यान्न की बबार्दी को कम करना, देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, फसलों की संकटकालीन बिक्री को रोकना और किसानों को उनकी फसलों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

- पांच वर्षों में सात करोड़ टन अन्न भंडारण की अतिरिक्त क्षमता होगी विकसित
- पोस्ट हार्वेस्टिंग में अनाज की होने वाली हजारों करोड़ रुपये की रुकेगी बर्बादी
- भंडारण क्षमता बढ़ाने में सहकारी क्षेत्र की भूमिका होगी अहम
- पैक्स बनाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोदाम, तीन चरणों में पूरी होगी योजना
- वर्तमान में खाद्यान्न की कुल पैदावार की मात्र 47 प्रतिशत ही भंडारण क्षमता

पहुंचता है और वहां से फिर गांव के राशन दुकानों तक पहुंचाया जाता है। इससे माल ढुलाई का खर्च दोगुना हो जाता है। गांव में जब गोदाम बन जाएंगे तो अनाजों को राशन की दुकानों तक पहुंचाने के खर्च में काफी कमी आएगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार, आगामी पांच वर्षों में देश में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता सात करोड़ टन तक हो जाएगी। इससे देश में खाद्यान्न की बबार्दी रोकने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सहकारिता क्षेत्र से और अधिक अपेक्षाएं है। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि यह एक भावना और चेतना है। सहकारिता जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को एक बड़ी औद्योगिक शक्ति में बदल सकती है। यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में अन्न भंडारण योजना बड़ा कदम है। इसके तहत देश में कोने-कोने में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। ये सभी काम कृषि के बुनियादी ढांचे को विस्तार देने में सहायक होंगे और उन्हें आधुनिक टेक्नॉलॉजी से जोड़ेंगे।

भंडारण क्षमता बढ़ने से मजबूत होगी खाद्य सुरक्षा

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान में फसल वित्त वर्ष 2024-25 में 33.09 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। भारत में खाद्यान्न भंडारण की कुल क्षमता केवल 14.49 करोड़ टन यानी करीब 47 प्रतिशत है, जबकि अन्य देशों में भंडारण क्षमता उत्पादन के मुकाबले 131 प्रतिशत तक है। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादक देशों में उत्पादन के मुकाबले भंडारण क्षमता अधिक है। देश में गोदामों की कम संख्या और अपर्याप्त भंडारण क्षमता की वजह से खाद्यान्न की बबादी होती है और किसानों पर अपने उपज के गैर-लाभकारी मूल्यों पर बेचने का दबाव भी रहता है। वैश्विक स्तर पर चीन में खाद्यान्न उत्पादन 61.5 करोड़ टन के मुकाबले भंडारण क्षमता 66 करोड़ टन है और अमेरिका में 42.2 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन के मुकाबले 68 करोड़ टन की भंडारण क्षमता है। ब्राजील, रूस, अर्जेंटीना, यूक्रेन, फ्रांस और कनाडा में भी खाद्यान्न उत्पादन के मुकाबले उनकी अन्न भंडारण क्षमता अधिक है। इनके मुकाबले भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में करीब 18 करोड़ टन खाद्यान्न भंडारण की कमी है।

खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद होने से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, जिसमें पैक्स, निजी क्षेत्र और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जैसी सरकारी एजेंसी शामिल होगी। स्थानीय स्तर पर सरकारी खरीद होने से स्थानीय जरूरतें भी वहीं से पूरी की जा सकेंगी। आसपास की मंडियों और रियायती दर की राशन दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए कम लागत में खाद्यान्न की सप्लाई की जा सकेगी। इससे जहां एक ओर महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी, वहीं सरकारी खजाने पर खाद्य सब्सिडी का बोझ भी घटेगा। पैक्स के स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाने से उपज बढ़ाने और फसल की बर्बादी को रोकने में

33.09
करोड़ टन खाद्यान्न का कुल उत्पादन

14.5
करोड़ टन ही है भंडारण क्षमता

18.59
करोड़ टन भंडारण क्षमता की आवश्यकता

सहायता मिलेगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष और कृषि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में पैक्स को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इससे गोदामों में अनाज के भंडारण से पहले अनाज की सफाई, अनाज की छंटाई और अनाज को सुखाने जैसे उपकरणों की खरीद की जा सकेगी। इससे भी रोजगार बढ़ेगा।

गोदाम निर्माण की नोडल एजेंसी है एनबीसीसी

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और सहकारिता मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के समन्वय से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना लागू की जा रही है। पूरी योजना के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सौंपा गया है। पीएम अन्न भंडारण योजना

अन्न भंडारण योजना से होगा

- **फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी:** उचित विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं से फसल कटाई के बाद खराब होने और कीटों के कारण अनाज की बबार्दी रोकने में मिलेगी।
- **खाद्य सुरक्षा में वृद्धि:** भंडारण में वृद्धि से स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और दबाव में कम कीमत पर बेचने की बजाय उचित समय पह बेहतर कीमत पर बेच सकेंगे।
- **पैक्स के गोदामों को खरीद केंद्र और राशन दुकान के रूप में मिलेगी मान्यता:** खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) में स्वीकृत पैक्स को अनाज खरीद केंद्र और उचित मूल्य की दुकान दोनों के रूप में मान्यता देने के आदेश जारी किए हैं। इससे परिवहन लागत कम होगी और ग्रामीण नागरिकों

देश की प्रमुख भंडारण एजेंसियां

- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
- केंद्रीय भंडारागार निगम (सीडब्लूसी)
- वेयरहाऊसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्लूडीआरए)
- स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन (एसडब्लूसी)
- रेलवे भंडारागार निगम के गोदाम
- राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदाम
- निजी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के गोदाम

व्यापक आर्थिक-सामाजिक बदलाव

की खाद्यान्न तक पहुंच आसान होगी।

- **सहकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** पैक्स इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर पर सहकारी संरचना मजबूत होगी।
- **बेहतर आपूर्ति श्रृंखला दक्षता:** सुव्यवस्थित भंडारण और वितरण से बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और बाजार पहुंच में सुधार होगा।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** इस योजना से कृषि उपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **रोजगार के नए अवसर:** ग्रामीण इलाकों में गोदामों के निर्माण एवं कृषि संबंधी अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

में अपनी भागीदारी को लेकर राज्यों ने उत्साह दिखाना शुरू कर दिया है। सहकारी क्षेत्र की संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नैफेड) ने आगे बढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय निर्माण एजेंसी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। एनबीसीसी सहकारिता क्षेत्र की निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के साथ मिलकर ग्रामीण भंडार गृहों का निर्माण कर रही है। सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में एनबीसीसी ने अब तक दो सौ से अधिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर लिया है।

दाल के गोदामों के साथ सब्जियों के कोल्डस्टोरेज भी

सहकारिता क्षेत्र की एजेंसी एनसीसीएफ दाल और सब्जियों के भंडारण के लिए अलग-अलग उत्पादक राज्यों में गोदाम बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। इसी तरह नैफेड ने भी अपने उत्पादक केंद्रों एवं मंडियों में पैक्स के साथ मिलकर गोदाम बनाने का फैसला किया है। इससे पैक्स को एक सुनिश्चित आमदनी की गारंटी प्राप्त हो जाएगी। विभिन्न राज्यों में एनसीसीएफ और नैफेड ने 2,500 से अधिक पैक्स को चिन्हित किया है जहां गोदाम बनाए जा सकते हैं। सब्जियों के गोदाम बनने से इसकी खेती को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

पारंपरिक फसलों की तुलना में सब्जी की खेती से ज्यादा आमदनी होती है। इसलिए युवा किसान इस ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि सब्जी भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से सब्जी उत्पादकों को कई बार भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था हो जाने से न सिर्फ आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकेगा बल्कि सब्जियों की बबार्दी भी रुकेगी। सहकारिता मंत्रालय की एक सूचना के मुताबिक, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने यहां पैक्स के साथ बनाए

जाने वाले गोदामों का निर्माण राज्य एजेंसियों से कराना चाहती है। उन्हें इसकी अनुमित दे दी गई है।

पीएम अन्न भंडारण योजना से पैक्स से जुड़े तकरीबन 13 करोड़ किसानों का लाभ होगा। सहकारी क्षेत्र से जुड़े इन किसानों को खेती के इनपुट खाद, बीज व कीटनाशक समेत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सहकारी संस्थाओं से होती है। देश के सभी पैक्स को 352 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों और 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों से तकरीबन पांच लाख करोड़ रुपये का सालाना ऋण वितरित किया जाता है। इसमें 1.3 लाख करोड़ रुपये नाबार्ड द्वारा रिफाइनेंस किया जाता है।

देश में खाद्यान्न भंडारण की कमी से देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों को भारी क्षति हुई है। भारत जितना अनाज पैदा करता है, उसका 50 प्रतिशत से भी कम भंडारण कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना से देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ेगा और गांवों में नए रोजगार पैदा होंगे। गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी समितियों (पैक्स) का है। फार्मगेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं के निर्माण में सहकारी सेक्टर को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाली है, जो किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लचीलापन, दक्षता और समृद्धि सुनिश्चित करेगी। सरकार का प्रयास ऐसे गांवों के निर्माण की तरफ भी बढ़ना है, जो सहकारिता के मॉडल पर चलकर आत्मनिर्भर बनें। ■

देशभर के सभी जिले भंडारण में होंगे सक्षम

देश के 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 430 जिलों में भंडारण की भारी कमी है, जिससे वहां के किसानों की मुश्किलें अधिक हैं। इन जिलों में लगभग 74,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। इन जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकता के बराबर भी अनाज का भंडारण नहीं होता है। जबकि इन जिलों में खाद्यान्न की पैदावार यहां कुल जरूरत के मुकाबले अधिक (सरप्लस) होती है। हालांकि देश में कुल पांच राज्यों के 134 जिलों में से नौ जिले ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त भंडारण क्षमता (सरप्लस) है।

खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में पंजाब एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र एक जिले में भंडारण की कमी है। इसी तरह हरियाणा के तीन जिलों में भंडारण की कमी है। जबकि पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से 22 जिले और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 64 जिलों में भंडारण की भारी कमी है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में खाद्यान्न भंडारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बाकी राज्यों में भंडारण की वास्तविक स्थिति नीचे टेबल के आंकड़ों से देखी जा सकती है।

खाद्यान्न भंडारण की सटीक निगरानी करेगा डिपो दर्पण

सहकार जागरण टीम

देशभर में मौजूद खाद्यान्न भंडारण डिपो में वैज्ञानिक और स्मार्ट भंडारण समाधान के लिए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग लगातार आधुनिक तरीके अपना रहा है। इसी सिलसिले में भंडारण व्यवस्था की सटीक निगरानी रखने के लिए इसे डिजिटल स्वरूप देने के तहत डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य भंडारण डिपो उच्चतम गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करें। यह डिपो प्रबंधकों को वास्तविक समय के आधार पर बुनियादी ढांचे, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा।

डिपो दर्पण को स्मार्ट वेयरहाउसिंग टेक्नोलॉजी के साथ विशिष्ट रूप से एकीकृत किया गया है जिससे एक निर्बाध डिजिटल निगरानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। इसमें सीसीटीवी से निगरानी और आईओटी सेंसर जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया गया है जिससे खाद्यान्न भंडारण में सुरक्षा और दक्षता दोनों सुनिश्चित होगी। आईओटी सेंसर के तहत गोदामों में परिवेश सेंसर, सीओ2 और फॉस्फीन सेंसर, आग सेंसर और शटर गेट सेंसर लगाया गया है। परिवेश सेंसर से अनाज की नमी और तापमान की निगरानी की जाएगी, जबकि सीओ2 सेंसर से अनाज के संभावित संक्रमण की निगरानी की जा सकेगी और फॉस्फीन गैस सेंसर विषाक्त गैस की पूर्व चेतावनी देगा। इसी तरह, तय समय के बाद गोदामों के दरवाजे खुलने की स्थित में गेट शटर सेंसर अलर्ट कर देगा जिसे अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सकेगा। गोदाम में आग लगने की स्थित में अग्नि सेंसर तुरंत अलर्ट जारी करेगा जिससे आग से होने वाले नुकसान को तुरंत रोका जा सकेगा।

डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप खाद्य भंडारण का वैज्ञानिक और स्मार्ट समाधान उपलब्ध कराएगा

इसके अलावा अनाजों की बोरियां गिनने के लिए एआई आधारित तकनीक, खाद्यान्न लाने एवं ले जाने वाले वाहनों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) और प्रवेश नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक (एफआरएस) को भी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर गोदामों में तैनात किया गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के स्वामित्व वाले तथा राज्य एजेंसियों एवं निजी क्षेत्र से किराये पर लिए गए गोदामों सहित कुल 2,278 गोदाम इस डिजिटल पहल में शामिल किए गए हैं।

डिपो दर्पण के माध्यम से डिपो प्रबंधक अपने डिपो में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के जियो टैग किए गए इनपुट को अपलोड करेंगे जिससे समय पर सुधार के लिए स्वचालित रेटिंग और एक्शन प्वाइंट तैयार हो जाएगा। इसके माध्यम से न सिर्फ डिपो प्रबंधक, बल्कि पर्यवेक्षी अधिकारी और तीसरे पक्ष के ऑडिटर भी किसी भी समय, कहीं से भी भंडार के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकेंगे जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। स्वचालित रिपोर्ट का उपयोग नियमित समीक्षाओं में किया जा सकेगा जिससे बुनियादी ढांचे और दक्षता में निरंतर और निर्बाध सुधार होता रहेगा।

इसमें शामिल गोदामों का मूल्यांकन दो श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा। पहला, इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी पहलू जिनमें सुरक्षा मानक, भंडारण की स्थिति, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और वैधानिक मापदंड शामिल हैं। दूसरा है परिचालन दक्षता पहलू जिसमें स्टॉक टर्नओवर, घाटा, स्थान उपयोग, जनशक्ति व्यय और लाभप्रदता शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से किया जाएगा तथा गोदाम को दोनों मापदंडों के समग्र स्कोरिंग के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी।

डिपो दर्पण भंडारण उत्कृष्टता का दर्पण है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बेहतर भंडारण और अधिक परिचालन दक्षता सुनिश्चित करेगा। वैज्ञानिक रूप से भंडारित प्रत्येक अनाज के साथ राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को यह सशक्त करेगा। ■

सहकारी समितियों की निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने पर श्री अमित शाह का जोर

एनसीईएल का निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य तय

सहकार जागरण टीम

भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए निर्यात में भी इन समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले दिनों एनसीईएल, एनसीओएल (राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड), बीबीएसएसएल (भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड) की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने यह

- **एनसीईएल को सहकारी चीनी मिलों से चीनी, त्रिपुरा के सुगंधित चावल, जैविक कपास और मोटा अनाज के निर्यात के नए अवसर तलाशने के निर्देश**
- **खाड़ी देशों को ताजी सब्जियों के निर्यात और आलू की विशेष किस्मों के लिए बड़ी कंपनियों के साथ भागीदारी का भी दिया सुझाव**
- **तीन ऐसे विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाए जिन्हें भारत से वर्तमान में निर्यात नहीं किया जा रहा: श्री अमित शाह**

लक्ष्य तय किया।

समीक्षा बैठक में श्री शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाए जिन्हें भारत से वर्तमान में निर्यात नहीं किया जा रहा है। साथ ही, सभी सहकारी संस्थाओं के निर्यात को एनसीईएल के माध्यम से ही करने का निर्देश दिया ताकि 20,000-30,000 करोड़ रुपए का कारोबार और टैक्स व संचालन लागत के बाद शुद्ध लाभ वापस सहकारी समितियों को मिल सके। बैठक में उन्होंने कहा कि एनसीईएल को सहकारी चीनी मिलों से

चीनी, त्रिपुरा के सुगंधित चावल, जैविक कपास और मोटे अनाज के निर्यात के नए अवसर तलाशने चाहिए। इसके अलावा, खाड़ी देशों में ताजी सब्जियों के निर्यात और आलू की विशेष किस्मों के लिए बड़ी कंपनियों के साथ भागीदारी की संभावनाओं का भी उन्होंने सुझाव दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने दलहन आयात के लिए अफ्रीका और म्यांमार में एनसीईएल के कार्यालय स्थापित करने तथा एक समर्पित वेबसाइट विकसित करने का भी सुझाव दिया, ताकि सहकारी सदस्य वैश्विक मांग को समझ सकें और अपनी आपूर्ति क्षमता साझा कर सकें।

एनसीईएल को मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अपने पहले वर्ष में ही इसने उल्लेखनीय प्रगति की। वित्त वर्ष 2024-25 में इसने 10,000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और 4,283 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिसमें 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। राष्ट्रीय स्तर की इस सहकारी संस्था ने 28 देशों में अपने निर्यात को बढ़ाया है। एनसीईएल द्वारा निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में बासमती और गैर-बासमती चावल, समुद्री उत्पाद (विशेषकर झींगा), मोटा अनाज, गेहूं, फल-सब्जियां, पशु उत्पाद, मसाले और बागान उत्पाद शामिल हैं। इसने सेनेगल, इंडोनेशिया तथा नेपाल के 61 आयातकों के साथ रणनीतिक समझौते (एमओयू) भी किए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2023 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से सहकारिता मंत्रालय द्वारा तीन नई राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को बनाया गया था, जिनका उद्देश्य सहकारी निर्यात, जैविक उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रचार के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करना है। श्री शाह ने कहा कि इनका संचालन संबंधित मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सहयोग से संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अनेक पहल एवं ऐतिहासिक योजनाओं की शुरूआत की है जिससे सहकारी क्षेत्र को तेज गति से बढ़ावा मिल रहा है।

ज्यादा उपज वाली बीजें विकसित करे बीबीएसएसएल

भारत के बीज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में बीबीएसएसएल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केला उत्पादक शीर्ष 10 राज्यों के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टिशू कल्चर सुविधा की स्थापना करना अति-आवश्यक है। गुजरात के कलोल में हाल ही में स्थापित किया गया अत्याधुनिक बीज अनुसंधान केंद्र अरहर, उड़द, मक्का जैसी फसलों की उच्च उपज, कम परिपक्वता और कम जल आवश्यकता वाली किस्मों के विकास के लिए कार्य करेगा। उन्होंने उच्च चीनी मात्रा और कम जल आवश्यकता वाली गन्ना किस्म पर भी कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, बीबीएसएसएल को एनडीडीबी और अमूल के नेटवर्क के माध्यम से बिक्री के लिए लचका चारा फसल के बीज विकसित करने का निर्देश दिया। प्रोसेसिंग किस्मों के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू जैसी प्रोसेसिंग किस्मों हेतु बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिये जाने पर भी उन्होंने बल दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने ब्रीडर सीड्स की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से समन्वय कर आवश्यक ब्रीडर बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

2024-25

में एनसीईएल ने 4,283 करोड़ रुपए का किया कारोबार

30,000

करोड़ रुपए तक कारोबार का लक्ष्य एनसीईएल के लिए निर्धारित

300

करोड़ रुपए से अधिक की कारोबार 2025-26 में करे एनसीओएल

एनसीओएल के लिए भी लक्ष्य तय

समीक्षा बैठक में एनसीओएल के संबंध में उन्होंने कहा कि एनसीओएल द्वारा प्राप्त जैविक उत्पाद अमूल, बिगबास्केट जैसे बड़े ब्रांडों को भी आपूर्ति किए जा रहे हैं जिससे 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के लिए अधिक मात्रा और लागत लाभ प्राप्त हो रहा है। जल्द ही इसके उत्पाद रिलायंस स्टोर्स में पूरे भारत में उपलब्ध होंगे। 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत वर्तमान में 22 उत्पाद दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध हैं। इसे प्रमुख महानगरों में लॉन्च करने की भी योजना है। इसके उत्पादों में अनाज, दालें, मसाले और मिठास उत्पाद शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एनसीओएल के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 300 करोड़ से अधिक के कारोबार का लक्ष्य रखा। उन्होंने राज्य स्तर पर प्रमाणित जैविक किसानों के समूह बनाने और उन्हें उच्च स्तर पर एकीकृत करने का भी निर्देश दिया है।

एनसीओल ने संचालन की शुरूआत के बाद से अब तक विभिन्न वर्गों में 7000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और 1,200 टन से अधिक की मात्रा का लेनदेन किया जो 2000 से अधिक किसानों से प्राप्त किया गया। इसका कारोबार अब तक 10.26 करोड़ रहा है।■

अब भारत के भीतर ही रहेगा सीमा पार बह रहा पानी

- आत्मनिर्भरता हमेशा से रही है हमारे आर्थिक डीएनए का हिस्सा
- भारत में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी एक साथ फल-फूल सकते हैं, दुनिया को दिखा रहा भारत
- भारत व्यापार और वाणिज्य का जीवंत केंद्र बन रहा है
- जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से सकल जन सशक्तिकरण (जीईपी) केंद्रित प्रगति की ओर बढ़ रहा भारत

सहकार जागरण टीम

देश की सीमा में ही बहेगा पानी- वाली पीएम की स्टोरी के इंट्रो की पहली लाइन के रूप में जोड़ें- भारत की सबसे बड़ी आकांक्षा वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनना है। राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रगतिशील सोच, मजबूत संकल्प और गहरी करुणा के साथ भारत तेजी से विकास के माध्यम से भविष्य का निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन विचारों को हाल ही में नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में दोहराते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता हमेशा से भारत के आर्थिक डीएनए का एक मूलभूत हिस्सा रही है। भारत के एक प्रमुख रक्षा निर्माता और निर्यातक के रूप में उभरा है। रक्षा उत्पादों का निर्यात 100 से अधिक देशों को होने लगा है। भारत के स्वदेशी नौसैनिक बेड़े की ताकत को रेखांकित किया, जिसमें आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरि शामिल हैं, जिन्हें पूरी तरह से घरेलू क्षमता के माध्यम से बनाया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आकांक्षा वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनना है। भारत की ताकत, संसाधनों और दृढ़ संकल्प के साथ स्वामी विवेकानंद के विचारों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने लोगों से उठने, जागने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक दृढ़ रहने का आग्रह किया। यह अटूट भावना आज हर नागरिक में दिखाई देती है। विकसित भारत की खोज में ऐसे समिट की भूमिका को सराहा। यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। दो प्रमुख खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह समझौता व्यापार और आर्थिक सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ेगा। दोनों देशों के विकास को गति मिलेगी। भारत के युवाओं के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। भारतीय व्यवसायों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत ने हाल ही में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के साथ व्यापार समझौते किए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि 'नदियों को आपस में जोड़ने' की महत्वपूर्ण पहल से नदियों को जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि इन पहलों से पानी की सुलभता सुनिश्चित करके लाखों किसानों को लाभ होगा। उन्होंने जल संसाधनों पर मीडिया में चल रही चर्चा का उल्लेख करते हुए अतीत की उस स्थिति को रेखांकित किया जब भारत के पानी का उचित हिस्सा उसकी सीमाओं से बाहर बह रहा था। उन्होंने कहा, 'भारत का पानी देश के भीतर ही रहेगा और देश के विकास के लिए अपने उचित उद्देश्य को पूरा करेगा।'

उन्होंने अतीत में वैश्विक राय, चुनावी आकलन और राजनीतिक

अस्तित्व की चिंताओं के कारण बड़े फैसले लेने में हुई देरी पर चिंता जताई। सच्ची प्रगति तब होती है जब निर्णय लेने का एकमात्र मानदंड 'राष्ट्र प्रथम' होता है। पिछले एक दशक में भारत ने इस सिद्धांत का पालन किया है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 'पिछले 10-11 वर्षों में, हमारी सरकार ने लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए गये हैं। जबकि वर्ष 2014 से पहले भारत के बैंक पतन के कगार पर थे। भारत का बैंकिंग क्षेत्र दुनिया में सबसे मजबूत है। बैंकों ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। इन सुधारों से जमाकताओं को लाभ हुआ है। एयर इंडिया की वित्तीय हालत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वह डूब रही थी। इससे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछली सरकारें सुधारात्मक कदम उठाने में हिचकिचा रही थीं। उनकी सरकार ने और अधिक नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक निर्णय लिए। हमारी सरकार के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए निर्धारित सरकारी धन का केवल 15 प्रतिशत ही वास्तव में गरीबों तक पहुंचता था। उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सारे लीकेज रोक दिया और उन्हें शत प्रतिशत उनका हक मिलता है। सरकारी रिकॉर्ड में 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हुआ करते थे। पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई प्रणाली की नीतिगत खामियों से ऐसा था। उनकी सरकार ने आधिकारिक रिकॉर्ड से इन 10 करोड़ झूठी प्रविष्टियों को हटा दिया। इस सुधार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का दुरुपयोग रोकने में मदद मिली है।

वर्ष 2014 से पहले लोकतंत्र और विकास के साथ साथ रहने पर संदेह जताने वालों को उन्होंने दिखा दिया कि भारत लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है जो कुछ भी कर सकता है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले लाखों छोटे उद्यमियों ने लोकतंत्र के सकारात्मक प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है।

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर जीईपी-केंद्रित प्रगति-लोगों के समग्र सशक्तिकरण-समाज के सामूहिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर रही है।' जब किसी गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है, तो उसका सशक्तिकरण और आत्म-सम्मान बढ़ता है। जब स्वच्छता सुविधाएं बनती हैं तो व्यक्ति खुले में शौच की अपमानजनक स्थिति से मुक्त हो जाता है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिलती है तो उनकी सबसे बड़ी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाती हैं।

सरकार के मूल दर्शन 'नागरिक देवो भव' के तहत उनका प्रशासन पुरानी 'माई-बाप' संस्कृति का पालन करने के बजाय नागरिकों को शासन के केंद्र के रूप में देखता है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को याद किया, जिन्हें पहले अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए हर साल कार्यालयों या बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन प्रमाण पत्र दूर से ही जमा कर सकते हैं। बिजली कनेक्शन, पानी के नल, बिलों का भुगतान, गैस सिलेंडर बुक करने और डिलीवरी प्राप्त करने जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन गया है। पिछले साल भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो एक दशक में लगभग दोगुना हो गया है। इस गति को और तेज करने के लिए, उन्होंने नवीनतम बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत की उत्पादन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ■

गुजरात व महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित समारोह में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह

वायब्रेंट गुजरात और मैग्नीफिसेंट महाराष्ट्र देश के विकास के मजबूत स्तंभ

सहकार जागरण टीम

उद्गम स्थल यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना नदी के जल को शुद्ध और पवित्र किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में साबरमती की तर्ज पर एक रिवरफ्रंट बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना का शुद्धिकरण न सिर्फ दिल्लीवासियों और पड़ोसी राज्यों के लिए बल्कि श्रीकृष्ण और यमुना जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्व रखता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित महाराष्ट्र व गुजरात दिवस पर अवसर पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र ने बिना कटुता के एक राज्य में से बने दो राज्यों के बीच स्वस्थ स्पर्धा और एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने साथ -साथ देश का विकास कैसे कर सकते हैं, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की सीमा, भाषा और संस्कृति को झगड़े का कारण बनाकर देश को तोड़ने वाले अपनी मंशा में सफल हो रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन सभी विचारों को नाकाम करते हुए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का जो संकल्प लिया है उसके परिणामस्वरूप आज हर भाषा और संस्कृति एक दूसरे से ताकत लेती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मराठी और गुजराती के बीच कोई स्पर्धा नहीं है और दोनों अपनी-अपनी जगह महान भाषाएं हैं। अगर व्यक्ति मन से ठान ले कि बिखराव लाने वाली हर चीज को समाप्त करना है तो उसका आदर्श उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की कल्पना देकर किया है। श्री शाह ने

- **गुजरात व महाराष्ट्र ने बिना कटुता के स्वस्थ स्पर्धा से किया देश का विकास**
- **छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र ने स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म का झंडा बुलंद किया**
- **यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना होगी साफ, साबरमती की तर्ज पर दिल्ली में बनेगा रिवरफ्रंट**
- **यमुना का शुद्धिकरण श्रीकृष्ण व यमुना के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण**

कहा कि 1 मई 1960 को मुंबई राज्य से दो राज्यों का जन्म हुआ। एक बना गौरवशाली गुजरात और दूसरा बना महान महाराष्ट्र। दोनों राज्यों का अनेक वर्षों से देश की हर समस्या को सुलझाने और विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना, केन्द्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

वीर छत्रपति की भूमि महाराष्ट्र ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाजीराव पेशवा से लेकर महाराष्ट्र के अन्य सेनानायकों ने मुगलों को मजबूत टक्कर देकर स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म का झंडा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज की सबसे पहली कल्पना युवा शिवाजी महाराज ने रखी और जब अंग्रेजों का शासन आया तब 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार' है, को लोकमान्य बाल गंगधार तिलक महाराज ने आगे बढ़ाया। श्री शाह ने कहा कि भक्ति आंदोलन हो या सामाजिक सुधार का प्रगतिशील मार्ग, ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी, सभी ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी एक अनन्य देशभक्त के रूप में देशभर के करोडों युवाओं के प्रेरणास्त्रोत बने।

> भारत के विकास में गुजरात और महाराष्ट्र का योगदान आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत बड़ा रहा है।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

गुजरात श्रीकृष्ण की कर्मभूमि और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जन्मभूमि रहा है। अनेक प्रकार के मजबूत साम्राज्यों ने गुजरात में जन्म लिया और महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल ने आजादी के पूरे आंदोलन को आकार दिया। आजादी के बाद विकास और देश को एक कर और मजबूती से जोड़कर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत आज इतना लंबा सफर तय कर सका है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत के विकास में गुजरात और महाराष्ट्र का योगदान आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत बड़ा रहा है। महाराष्ट्र में गरबा भी उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और गुजरात में गणेश उत्सव के दौरान सम्मान के साथ घर घर गणपति लाए जाते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों राज्य देश के आर्थिक विकास का बहुत मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हैं। महाराष्ट्र हमेशा से देश की आर्थिक राजधानी रहा है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि गुजरात की जीएसडीपी भी 30 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। वह देश का तीसरा संबसे बड़ा अर्थतंत्र है। गुजरात में सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ी रिफायनरी, एशिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, सबसे पहली बुलेट ट्रेन, सबसे पहली गिफ्ट सिटी और अब धोलेरा स्मार्ट सिटी भी गुजरात में बन रही है। वायब्रेंट गुजरात और मैग्नीफिसेंट महाराष्ट्र देश के विकास के मजबूत स्तंभ बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने 2047 तक अपने विकास के रोडमैप का खाका फाइनल कर दिया है।

गुजरात और महाराष्ट्र ने अपनी विरासत को संभालते हुए आधुनिकता को स्वीकार करने के साथ ही देश की एकता और अखंडता में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री की महान भारत की कल्पना में राज्यों के बीच विकास की स्वस्थ स्पर्धा और उसके माध्यम से देश के विकास के सूत्र को दोनों राज्यों ने स्वीकार किया है। श्री शाह ने कहा कि 2047 में जब भारत एक विकसित देश बनेगा तब गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का इसमें सबसे अधिक योगदान होगा। ■

वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन (ग्लेक्स) में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

'वसुधैव कुटुंबकम' के प्राचीन दर्शन में निहित है भारत का अंतरिक्ष विजन

सहकार जागरण टीम

भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अभूतपूर्व अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा और वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर अपने पदचिह्न छोड़ेगा। भारत की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में मंगल और शुक्र प्रमुख लक्ष्य बने रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन बड़ी घोषणाओं को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन (ग्लेक्स) 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए किया। श्री मोदी ने दुनिया भर से आए विशिष्ट प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों से देश की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रगति को साझा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष केवल एक गंतव्य नहीं है, बल्कि जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति की घोषणा है। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुम्बकम' के प्राचीन दर्शन में निहित है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल अपने विकास के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक ज्ञान को समृद्ध करने, साझा चुनौतियों का समाधान करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के बारे में है। सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने एक बेहतर भविष्य के लिए सामूहिक आकांक्षा के अनुरूप अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय शुरू करने का आह्वान किया और कहा कि भारत एक साथ सपने देखने, एक साथ निर्माण करने और एक साथ सितारों तक पहुंचने के लिए खड़ा है।

- **अंतरिक्ष केवल एक गंतव्य नहीं है, बल्कि जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति की घोषणा है**
- **भारत के रॉकेट सिर्फ पेलोड नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को भी साथ ले जाते हैं**

उन्होंने कहा कि भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन, 'गगनयान' अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है। वर्ष 1963 में एक छोटे रॉकेट को लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव

के पास उतरने वाला पहला देश बनने तक भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां इसी भावना पर केंद्रित हैं। भारत के रॉकेट सिर्फ पेलोड नहीं ले जाते, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को भी साथ ले जाते हैं। भारत की अंतरिक्ष प्रगति और उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि मानवीय भावना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकती है। उन्होंने 2014 में अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने की भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद किया और कहा कि चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में मदद की, चंद्रयान-2 ने चंद्र सतह की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें दीं और चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर हमारी समझ को गहराई दी। उन्होंने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए, एक ही मिशन में 100 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया और भारतीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग करके 34 देशों के लिए 400 से अधिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को डॉक करने की भारत की नवीनतम उपलब्धि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा कदम बताया। ■

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2035 तक अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा और वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पदचिह्न छोड़ेगा

देश का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन 'गगनयान' अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारी बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है

देश में अब उपग्रह प्रौद्योगिकी, प्रणोदन प्रणाली, इमेजिंग और अन्य अग्रणी क्षेत्रों में योगदान दे रहे 250 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप्स

महिला वैज्ञानिकों के हाथों में कई अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व

प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि भारत के कई अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के लिए अंतरिक्ष का मतलब सिर्फ खोज करना नहीं, बल्कि सशक्तिकरण भी है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शासन और आजीविका में सुधार लाती है और पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्होंने मछुआरों को सतर्क करने के लिए अपनाई गई चेतावनी की व्यवस्था, गतिशक्ति प्लेटफॉर्म, रेलवे सुरक्षा और मौसम की भविष्यवाणी में उपग्रहों के योगदान का जिक्र किया और कहा कि प्रत्येक भारतीय के कल्याण को सुनिश्चित करने में इन उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को स्टार्टअप, उद्यमियों और युवा प्रतिभाओं के लिए खोलकर नवाचार को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत में अब 250 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं जो उपग्रह प्रौद्योगिकी, प्रणोदन प्रणाली, इमेजिंग और अन्य अग्रणी क्षेत्रों में प्रगति में योगदान दे रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के बारे में है। उन्होंने मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज के सामूहिक लक्ष्य पर जोर दिया। दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान शुरू किया गया जी20 सैटेलाइट मिशन, ग्लोबल साउथ में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

विश्व यकृत दिवस के मौके पर आईएलबीएस में बोले श्री अमित शाह

स्वस्थ शरीर का गेटवे है स्वस्थ लिवर

सहकार जागरण टीम

यकृत हमारे शरीर की रचना और इसे स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के सभी अंगों में पुनर्जीवित होने की सबसे अधिक क्षमता यकृत में है क्योंकि यकृत ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का मार्ग है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को विश्व यकृत दिवस के मौके पर 'इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज' (आईएलबीएस) के एक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक ऐसे विकसित भारत का लक्ष्य रखा है जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर विश्व का नेतृत्व करे। विकसित भारत की संकल्पना रोगग्रस्त होकर नहीं की जा सकती और इसीलिए यह बहुत

- **सभी देशवासी अच्छा आहार, पर्याप्त पानी, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम करें**
- **हमारे वेदों में दिए गए 'आहार ही औषधि है' के मंत्र को अपनाकर आगे बढ़ रहा है पूरा विश्व**
- **लिवर रोग से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल 'हील्ड' की शुरूआत**
- **सभी व्यक्तियों को नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान विटामिन ई की भी जांच करानी चाहिए**

जरूरी है कि हर नागरिक स्वस्थ रहे। श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए इस दिशा में ठोस पहल किए हैं। इसके लिए पिछले 10 वर्षों में अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन वर्षों में देश के 140 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक आवरण की रचना की है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी अच्छा आहार, पर्याप्त पानी, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम करें, बाकि आपके स्वास्थ्य की चिंता सरकार करेगी।

इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों को अपने यकृत के प्रति सजग और जागरूक रहते हुए पूरी जानकारी के साथ इसे स्वस्थ रखने

देश के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनेक योजनाएं

श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से 2025 तक 11 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के साथ देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाने के अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। सरकार एक ऐसी पद्धति विकसित करने पर फोकस कर रही है जिससे कि हम बीमार ही न हों। श्री शाह ने कहा कि आज बड़े-बड़े एलोपैथिक अस्पताल भी अपने यहां आयुष का विंग खोल रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों को पांच लाख रुपए तक के इलाज का पूरा खर्च मोदी सरकार दे रही है। 70 साल से अधिक आयु वाले नागरिको के इलाज के लिए भी पांच लाख तक का सभी खर्च सरकार उठा रही है।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में देश में जहां सात एम्स थे, आज 23 हैं, मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 हैं, एमबीबीएस सीटें 51 हजार थीं जो आज एक लाख 18 हजार हो गई हैं और अब इनमें 75 हजार सीटें और बढ़ने जा रही हैं। इसके साथ-साथ, पीजी की सीटें 31 हजार थीं जो आज बढ़कर 74 हजार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में देश का स्वास्थ्य का बजट 37 हजार करोड़ रुपए था जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर आज एक लाख 27 हजार करोड़ रुपए कर दिया है।

10

वर्षों में देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए सरकार ने चलाए अनेक कार्यक्रम

का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री शाह ने कहा शरीर की आवश्यकता के अनुसार जल, आहार, व्यायाम और नींद से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मई 2020 से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।

श्री शाह ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ने 'हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल-एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन' (एचईएएलडी) के शुभारंभ के साथ एक मील का पत्थर स्थापित किया, जो विश्व लिवर दिवस के अवसर पर भारत में लिवर रोग से निपटने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी पहल है। यह अभिनव पहल यकृत को स्वस्थ रखने के प्रति देश में जागरूकता फैलाने में सफल होगी। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामुदायिक आउटरीच और नीति सुधार को लिवर की देखभाल में एकीकृत करके शराब पर निर्भरता से जुड़े कलंक को कम करना भी है। यह पहल जागरूकता, रोकथाम, पुनर्वास और नीति एकीकरण के माध्यम से बीमारी से निपटने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान विटामिन ई की भी जांच करवानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि हमारे वेदों में कहा गया है कि 'आहार ही औषधि है' और इस थीम को स्वीकार कर आज पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है।

देशवासियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए सजग है मोदी सरकार

श्री शाह ने कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 65 हजार करोड़ रुपए खर्च कर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक कंप्लीट यूनिट बनाने की व्यवस्था की है। जेनेरिक दवाओं के लिए देश में 15 हजार से अधिक जनऔषधि केंद्रों का नेटवर्क तैयार कर 80 प्रतिशत तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बच्चे के जन्म से 15 साल की आयु तक मिशन इंद्रधनुष के तहत उसके मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की गई और एक करोड़ 32 लाख माताओं का भी टीकाकरण हुआ। ई-संजीवनी ऐप के तहत देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्वास्थ्य संस्थानों ने 30 करोड़ 90 लाख से अधिक डिजिटल डॉक्टरी परामर्श दिया है।

श्री शाह ने मीडिया से भी मनोरंजन के साथ-साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की और कहा कि आईएलबीएस को देशभर के एम्स और प्रमुख सरकारी अस्पतालों के साथ जुड़कर लिवर के रोगियों के मार्गदर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए और इसके प्रति जागरूकता फैलाना के प्रयास करने चाहिए। ■

पंचायती राज दिवस पर बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 10 साल में मिली नई गति

सहकार जागरण टीम

- **पंचायतों को सशक्त करने के लिए उठाए गए अनेक कदम, पंचायतों को तकनीक के माध्यम से किया गया मजबूत**
- **बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ**

बीते दशक में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। पंचायतों को मजबूत बनाने में टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में किया। उन्होंने 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि ये विकास परियोजनाएं बिजली, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इससे बिहार में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस दृढ़ विश्वास की ओर ध्यान दिलाया कि भारत का तीव्र विकास तभी संभव है जब इसके गांव मजबूत हों। पंचायती राज की अवधारणा इसी भावना में निहित है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछले एक दशक में दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी हैं। गांवों में 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। पंचायतों के डिजिटलीकरण से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों तक आसान पहुंच जैसे अतिरिक्त लाभ हुए हैं। देश भर में 30,000 नए पंचायत भवन बनाए गए हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि पंचायतों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। पिछले एक दशक में पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है जिसका उपयोग गांवों के विकास के लिए किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सामने सबसे बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी है। इस समस्या के समाधान के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इससे अनावश्यक विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिली है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायतों ने सामाजिक भागीदारी को मजबूत किया है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसकी बदौलत आज बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दलितों, महादलितों, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों की महिलाएं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण

प्रदान करने वाला कानून भी बनाया गया है। इससे सभी राज्यों की महिलाओं को लाभ होगा और उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

मोदी सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने और रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में 'जीविका दीदी' कार्यक्रम ने अनेक महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। बिहार में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को और मजबूत करेगा और देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में योगदान देगा।

तीन करोड़ और गरीबों को जल्द मिलेगा पक्का घर

बीते एक दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने नई गति प्राप्त की है। गांवों में गरीबों के लिए घर, सड़कें, गैस कनेक्शन, पानी के कनेक्शन और शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों करोड़ रुपए आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे मजदूरों, किसानों, वाहन चालकों और दुकानदारों को लाभ हुआ है और उन्हें आय के नए रास्ते मिले हैं। इससे विशेष रूप से उन समुदायों को लाभ हुआ है जो पीढ़ियों से वंचित थे।

श्री मोदी ने आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी परिवार बेघर न रहे और सभी के सिर पर पक्की छत हो। पिछले एक दशक में इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। अकेले बिहार में 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। श्री मोदी ने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के घर दिए जाएंगे। देश भर में 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें बिहार के 3.5 लाख लाभार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घरों के लिए वित्तीय सहायता भेजी गई है, जिनमें बिहार के 80,000 ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'बीता दशक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का दशक रहा है। भारत रेलवे, सड़क और हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पटना में मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं और देश भर के दो दर्जन से अधिक शहर अब मेट्रो सुविधाओं से जुड़ चुके हैं।' उन्होंने पटना और जयनगर के बीच 'नमो भारत रैपिड रेल' सेवा शुरू करने की घोषणा की। साथ ही, बिहार में कई नई रेल लाइनों के उद्घाटन और शुभारंभ किया। इसमें सहरसा और मुंबई के बीच आधुनिक अमृत भारत ट्रेन सेवा की शुरूआत भी शामिल है। सरकार मधुबनी और झंझारपुर सहित बिहार के कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दरभंगा हवाई अड्डे से मिथिला और बिहार में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। ये विकास परियोजनाएं बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

15

लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र किए जारी

श्री मोदी ने कहा, 'किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह रीढ़ जितनी मजबूत होगी, गांव उतना ही मजबूत होगा और परिणामस्वरूप राष्ट्र भी मजबूत होगा।' उन्होंने कहा कि मिथिला का सांस्कृतिक प्रधान खाद्य पदार्थ मखाना अब सुपरफूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है, जो इसे आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र के उत्पाद के रूप में प्रमाणित करता है। मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। उन्होंने मखाना बोर्ड को लेकर बजट में की गई घोषणा पर भी प्रकाश डाला, जिससे मखाना किसानों की किस्मत बदलने की उम्मीद है। साथ ही बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। ■

नई दिल्ली में बोडोफा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री अमित शाह ने कहा

बोडोफा की प्रतिमा देशभर के जनजातीय समाज के आत्मसम्मान का प्रतीक

- बोडो समझौते के 96 प्रतिशत मुद्दों का हो गया समाधान, जल्द ही शत-प्रतिशत मुद्दे हो जाएंगे हल
- 'जियो और जीने दो' के सूत्र के साथ बाथो धर्म की मूल संकल्पना को आगे बढ़ाएं बोडो युवा

सहकार जागरण टीम

पूरा जीवन अपनी जाति और क्षेत्र के सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म की 35वीं पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उनकी आदमकद प्रतिमा का अनारवण किया। राजधानी दिल्ली के महत्वपूर्ण मार्ग का नाम बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग भी रखा गया। श्री शाह ने कहा कि बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमा सिर्फ बोडोलैंड ही नहीं बल्कि अपनी भाषा और धर्म के विकास के लिए संघर्ष करने वाले देश के सभी लोगों का सम्मान है। नई दिल्ली में बोडोफा की प्रतिमा देशभर के जनजातीय समाज के आत्मसम्मान का प्रतीक है।

पहलगाम आतंकी हमले की भेंट चढ़े नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री शाह ने परिजनों से कहा कि यह केवल उनकी क्षति नहीं है बल्कि पूरे देश की क्षति है। पहलगाम में मारे गए लोगों के प्राणों की क्षति का जितना दर्द उनके परिजनों के दिल में है उतना ही देश के हर नागरिक के दिल में है। कश्मीर में आतंकवाद में खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने कहा कि आतंकवादी यह न समझ लें कि आज हमारे नागरिकों की जान लेकर वे यह लड़ाई जीत गए हैं। श्री शाह ने कहा कि यह लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि मुकाम है। आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार हर व्यक्ति को चुन-चुनकर जवाब दिया भी जाएगा और उससे जवाब लिया भी जाएगा।

श्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे उत्तरपूर्व हो, वामपंथी उग्रवाद हो या फिर कश्मीर में आतंकवाद हो, इन सबका मजबूती से जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि

कायराना हमला करके कोई अगर यह समझता है कि उनकी जीत हो गई है तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह मोदी सरकार है जो किसी को बख्शेगी नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की भूमि से आतंकवाद को समूल उखाड़ फेंकने का मोदी सरकार का संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। इस लड़ाई में न सिर्फ 140 करोड़ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। दुनिया के सभी देश एकजुट होकर आतकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है उन्हें निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा।

बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म की नौ फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्होंने कहा कि बोडोफा न सिर्फ बोड़ोलैंड और बोड़ो जाति बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे आदिवासी समाज को एकजुट कर अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने की शिक्षा दी। बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजातियों के लोगों को एकत्रित किया। बोडोफा आज नहीं हैं लेकिन उनके जियो और जीने दो के सूत्र को पूरे बोड़ोलैंड और आदिवासी समाज ने स्वीकार किया है। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोड़ोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। असम बोड़ोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोड़ोलैंड असम को स्वीकारता है। इस देश पर बोड़ो लोगों का उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि 2014 से देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का मानना है कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है और इसी सूत्र के तहत आज बोड़ोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है।

नौ महीने की व्यापक चर्चा के बाद 2020 में बोडो समझौता हुआ जिसके तहत सभी

लोग हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। मोदी सरकार समझौते का पालन भी करती है। उन्होंने कहा कि बोड़ो समझौते के 96 प्रतिशत मुद्दे को हमने क्लीयर कर दिए हैं और जल्द ही शत प्रतिशत मुद्दों को हल कर देंगे। श्री शाह ने कहा कि असम और नॉर्थईस्ट के लोगों को मोदी सरकार की यह बहुत बड़ी भेंट है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नॉर्थईस्ट में 20 से अधिक समझौते किए हैं और 10 हजार से अधिक लोग हथियार डालकर मुख्यधारा में आए हैं। 20 से अधिक समझौतों में 78 प्रतिशत मुद्दों की पूर्ति पिछले 3-4 साल में मोदी सरकार ने की है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। पूरा असम अब शांति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है।

बोड़ो युवाओं को 'जियो और जीने दो' के सूत्र की याद दिलाते हुए श्री शाह ने कहा कि बाथो धर्म की मूल कल्पना को आगे बढ़ाना चाहिए। असम के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। असम पूरे दश में औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है। असम में कई उद्योग विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थईस्ट में 220 से अधिक जातीय समूह, 160 से अधिक जनजातियां, 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां, 50 से अधिक यूनिक त्यौहार, 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां और 100 से अधिक स्वादिष्ट व्यंजन हैं।

गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थईस्ट और असम की संस्कृति भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। सरकार ने असम और नॉर्थईस्ट के विकास के लिए कई काम किए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 50 से अधिक बार नॉर्थईस्ट का दौरा कर चुके हैं। श्री शाह ने कहा कि बोड़ोलैंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार गए हैं। नॉर्थईस्ट की संस्कृति और ताकत अनमोल हैं और नॉर्थईस्ट के विकास में पूरे देश की ताकत लगे मोदी सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है।■

अमरावती में आयोजित एक समारोह में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गरीब, किसान, युवा और महिला शक्ति से होगा विकसित भारत का निर्माण

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि अमरावती एक ऐसी भूमि है जहां परंपरा और प्रगति साथ-साथ चलती है और यह बौद्ध विरासत की शांति व विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा को समेटे हुए है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से आधुनिकीकरण करने वाले बुनियादी ढांचे वाले देशों में से एक है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने भौतिक, डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रगति से आंध्र प्रदेश भी काफी लाभान्वित हो रहा है। आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की सड़क और रेल परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिससे इसके विकास में तेजी आई है। श्री मोदी ने कहा, 'आंध्र प्रदेश कनेक्टिविटी के नए युग का गवाह बन रहा है, जो जिले-दर-जिले संपर्क को बढ़ाएगा और पड़ोसी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।' इससे किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंच आसान लगेगी और उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता से लाभ होगा। पर्यटन और तीर्थयात्रा क्षेत्र भी गति पकड़ेंगे, जिससे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा।

▶▶ भारत का पिछले 10 वर्षों से भौतिक, डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस

श्री मोदी ने रेलवे परियोजनाएं भी देश को समर्पित कीं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो सड़क सुरक्षा को और बढ़ाएंगी; रोजगार के अवसर पैदा करेंगी; तिरुपति, श्रीकालहस्ती, मालाकोंडा और उदयगिरि किले जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश

की आकांक्षाओं और भारत के विकास की संकल्पना की मजबूत नींव हैं। प्रधानमंत्री ने छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेलवे परियोजना की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बुनियाद रखी, जिनमें विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, अन्य प्रशासनिक भवन और 5,200 से अधिक परिवारों के लिए आवास भवन शामिल हैं। श्री मोदी ने मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखी। उन्होंने विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की बुनियाद भी रखी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना और स्वदेशी उत्पादों की बाजार में उपस्थिति बढ़ाना है।

श्री मोदी ने घोषणा की कि विशाखापत्तनम में जल्द ही अपना एकता मॉल होगा, जहां पूरे भारत के कारीगर और शिल्पकार एक ही छत के नीचे अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकेंगे। ये मॉल लोगों को भारत की समृद्ध विविधता से जोड़ेंगे, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की कल्पना को मजबूत करेंगे।

परंपरा और प्रगति की भूमि है अमरावती

श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में अमरावती सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, स्वच्छ उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी शहर के रूप में उभरेगा और यहां प्रदेश के युवाओं के सपने साकार होंगे। भारत सरकार इन क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने में राज्य सरकार को पूरा सहयोग दे रही है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अमरावती स्वर्ण आंध्र की कल्पना को ऊर्जा प्रदान करेगा और इसे प्रगति और परिवर्तन का केंद्र बनाएगा। उन्होंने कहा, 'अमरावती सिर्फ एक शहर नहीं है, यह वह ताकत है जो आंध्र प्रदेश को एक आधुनिक राज्य में बदल देगी और एक शक्ति जो आंध्र प्रदेश को एक उन्नत राज्य में बदल देगी।'

बुनियादी ढांचे के विकास से उद्योगों को मजबूती

बुनियादी ढांचे के विकास के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों को काफी लाभ होता है। इससे भारत के युवाओं को सीधे लाभ होता है, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भर में सिंचाई परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत नदी-जोड़ने की पहल शुरू कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर खेत तक पानी पहुंचे और किसानों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। नई राज्य सरकार के गठन के साथ पोलावरम परियोजना ने नये सिरे से गति पकड़ी है।

भारत को अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया हर मिशन लाखों भारतीयों को गर्व से भर देता है और इससे देश के युवाओं को अंतरिक्ष अन्वेषण की ओर प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि एक नया रक्षा संस्थान स्थापित किया गया है। नागायलंका में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज- नव दुर्गा परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेगी।

किसानों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता

श्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किए अपने संकल्पों को दोहराते हुए कहा, 'विकसित भारत की नींव चार प्रमुख स्तंभों- गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण पर टिकी है।' ये सभी सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं, जिसमें किसानों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए लगभग 12 लाख करोड़ खर्च किए हैं। किसानों को हजारों नए और उन्नत बीज वितरित किए गए हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत, आंध्र प्रदेश के किसानों को 5,500 करोड़ रुपए का दावा निपटान मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आंध्र प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में सीधे 17,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है, जिससे उनकी आजीविका सुनिश्चित हुई है।■

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सहकारी समितियों में बढ़ेगी पारदर्शिता

पैक्स का किया जा रहा कंप्युटरीकरण, सहकारी संस्थाओं का भी हो रहा डिजिटलीकरण

सहकार जागरण टीम

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पैक्स का कंप्युटरीकरण करने के अलावा सहकारी बैंकों और संस्थाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही, देशभर में मौजूद सहकारी संस्थाओं का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल का कहना है कि देशभर की सभी सहकारी संस्थाओं में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक लंबा इतिहास रहा है। खासकर, सहकारी बैंकों के घोटालों से इस क्षेत्र पर लोगों का भरोसा घटा जिसे फिर से बहाल करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से कई पहल की गई है।

'सहकार जागरण' से विशेष बातचीत में श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, 'सहकारिता के मूल स्वरूप को अगर देखें तो यह पूरा क्षेत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। जितना आप लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे, सहकारिता क्षेत्र को ज्यादा ताकत दे सकते हैं। लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटी को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के माध्यम से आने वाले वर्षों में जो स्किल्ड मैनपावर आएगा उससे इस क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा। आज कई सोसायटी में कार्य क्षमता की कमी है, प्रबंधन में अनियमितता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कम है। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जिससे उनके कार्य में पारदर्शिता नहीं है। इसका समाधान हमने यह निकाला है कि सभी पैक्स का कंप्युटरीकरण किया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही काम करना है जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं रहेगा। यह सब होने के बाद सहकारिता क्षेत्र को अच्छी दिशा मिलेगी।'

श्री मोहोल ने सहकारी बैंकों के बारे में कहा कि पहले इनका नियमन राज्य सरकारों के कानूनों से होता जिसमें बदलाव किया गया और इनकी निगरानी की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई। रिजर्व बैंक सख्ती के साथ नियमों का पालन कर रहा है और गड़बड़ी करने वाले बैंकों के खिलाफ कड़े कदम भी उठा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी नाबार्ड के माध्यम से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की मदद की जाती है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की मदद की कोई संस्था ही नहीं थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इनकी मदद के लिए एक अंब्रैला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम (एनयूसीडीएफसी) का गठन किया जो सहकारी बैंकों के लिए एक नियामक की तरह काम करेगा। यह न सिर्फ उनकी आर्थिक रूप से सहायता करेगा, बल्कि उन्हें तकनीकी एवं बुनियादी सहायता देगा और उनकी निगरानी भी करेगा। इससे सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। सहकारी बैंकों में सुधार के लिए सहकारिता मंत्रालय ने और भी कई पहलें की हैं और उन्हें सामान्य बैंकों की तरह सेवाएं देने लायक बनाने के लिए कई नए रास्ते खोले हैं। ये कदम लोगों का टूटा भरोसा बहाल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे।■

जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे रहा एनसीओएल

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक उत्पादक देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय स्तर पर नई सहकारी संस्था राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना की गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को सशक्त बनाने और पूरे भारत में वास्तविक जैविक उत्पादों तक बाजार की पहुंच बढ़ाने में एनसीओएल का योगदान बढ़ता जा रहा है।

केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एनओसीएल की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह संयंत्र स्वच्छता और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा। यहां 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के दालों और जैविक खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पैकेजिंग की जा सकेगी। यह संयंत्र उच्च गुणवत्ता वाले टिकाऊ जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और वितरित करने के लिए एनसीओएल की यात्रा में मील का पत्थर है। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड स्वस्थ भारत के लिए सभी को स्वस्थ भोजन सुलभ करा रहा है। डॉ. भूटानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय किसानों की जैविक उपज को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई पहल कर रहा है। एनसीओएल की पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन प्राथमिक उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करते हुए परिचालन को बढ़ाने और प्रमाणित जैविक उपज की पहुंच का विस्तार करने के संगठन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू हुआ एनसीओएल का अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा संयंत्र
- स्वच्छता और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों के साथ होगी भारत ऑर्गेनिक्स के उत्पादों की पैकेजिंग

सहकारी क्षेत्र का होने के कारण एनसीओएल अपने उद्यम का लाभ अपने सदस्य किसानों तक पहुंचा रहा है। इससे किसानों को अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 21 उत्पाद एनसीसीएफ एवं नैफेड के सभी आउटलेट्स पर और दिल्ली-एनसीआर में सफल के 200 से अधिक आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं। जल्द ही रिलायंस के सभी आउटलेट्स पर भी ये उत्पाद मिलने लगेंगे। इन्हें स्विगी, ब्लिंकिट, बिगबास्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया जा रहा है। भारत ऑर्गेनिक्स के उत्पादों में दाल, अनाज, मसाले, स्वीटनर्स आदि प्रमुख हैं। एनसीसीएफ और नैफेड एनसीओएल के प्रमोटर सदस्य हैं।

एनसीओएल के अध्यक्ष श्री मीनेश शाह ने इस अवसर पर कहा कि एनसीओएल का लक्ष्य किसानों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति उनकी कड़ी मेहनत का प्रीमियम मूल्य दिलाना और जैविक खाद्य को भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सस्ता और सुलभ बनाना है। एनसीओएल भारत ब्रांड के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों की प्रामाणिकता पर अतिरिक्त जोर देता है। इसके तहत प्रत्येक बैच में 245 से अधिक कीटनाशक अवशेषों का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाता है। एनसीओएल के प्रबंध निदेशक श्री विपुल मित्तल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सहाकारिता वर्ष के अवसर पर 'भारत ऑर्गेनिक्स' के उत्पादों के पैकेट पर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो भी प्रिंट किया जा रहा है। साथ ही उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए एक क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है। उपभोक्ता इस कोड को स्कैन करके उक्त बैच की परीक्षण रिपोर्ट देख सकते हैं।

विशेष आलेख

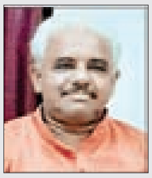

राजदत्त पांडे

अन्न भंडारण क्षमता विस्तार में सहकारिता की बड़ी भूमिका

नये सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां सक्रिय होने लगी हैं जिससे लोगों की आमदनी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिली है। वैसे तो भारत में सहकारिता आंदोलन ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। इसी का नतीजा है कि देश चीनी, दुग्ध, ऋण एवं उर्वरक आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महान शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। अनेक सहकारी ब्रांड केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी घर-घर प्रचलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को सहकारिता मंत्रालय ने अपना आदर्श मंत्र बना लिया है।

सहकारिता के भविष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सरकार की ओर से अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी समितियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय अहम भूमिका निभा रही है। एक लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की पीएम अन्न भंडारण योजना लांच हो गई है, जिसके निर्माण और संचालन का पूरा दायित्व सहकारी क्षेत्र पर डाल दिया गया है। पैक्स की भागीदारी से खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विस्तार होने से देश की खाद्य सुरक्षा को पुख्ता बनाने में मदद बड़ी मिलेगी। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम बनाने की योजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। दरअसल, पुराने सहकारी गोदामों में जहां पहले गरीब किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से बोआई के समय अनाज उधार में दिया जाता था, उसकी जगह अब किसानों के सरप्लस अनाज को नये गोदामों में रखा जाएगा। किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए उधारी के रूप में नगदी दी जाती है। देश में सहकारिता के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित हो रहे हैं। किसानों को बिचौलियों और सूदखोरों से बचाने के लिए रियायती दरों पर उन्हें पर्याप्त ऋण भी प्रदान किया जा रहा है।

भारत में सहकारिता का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। आजादी से पूर्व भी भारत के कई भागों में सहकारिता का प्रचलन था। इसकी अवधारणा और सहकारिता पर आधारित गतिविधियां लोगों के सहकारी जीवन के अंग के रूप में व्यवहार में अपनाई जाती थी। ग्रामीण समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से बनाए जाने. वाले जलाशय या वन आदि आम तौर पर पाए जाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जोड़कर समूह बनाने के पीछे का विचार यह था कि नई और स्वैच्छिक महत्वपूर्ण समझ बन सके जिससे समूह गारंटी प्रस्तुत कर सकेंगे और ऋणदाताओं को भी व्यक्ति की बजाए समूह को ऋण देना कम जोखिम भरा लगेगा। इस दिशा में एक लंबी विकास यात्रा के बाद देश में सहकारी ऋण समिति अधिनियम के माध्यम से कानून बना, जो शुरूआत में केवल ऋण संबंधी सहकारी संगठनों तक सीमित था। वर्ष 1911 तक भारत में 5300 समितियां बन चुकीं थीं, जिनमें 3 लाख से अधिक सदस्य थे।

देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता के विकास को बल मिला, योजना आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं को समेटने के लिए संगठन की सहकारी पद्धति को अपनाने पर बल दिया। इसने शहरी सहकारी बैंकों, कामगारों की सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों, आवास सहकारी समितियों,सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था की और यह सिफारिश की गई, जिससे प्रत्येक विभाग सहकारी समितियों के निर्माण की नीति का अनुसरण करे। सहकारिता राज्य का विषय होने तथा प्रत्येक राज्य में अपने सहकारिता संबंधी कानून होने के कारण मॉडल सहकारी समिति अधिनियम के मसौदे को सभी राज्य सरकारों को विचार करने तथा राज्य स्तर पर लागू करने के लिए भेजा गया। सहकारी समितियों की सामूहिकता को बढ़ावा देने और देश के सामाजिक पूंजी आधार को संरक्षित करने में एक अग्रणी भूमिका है।

वास्तव में, सामूहिकता और लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिये सहकारिता सबसे अच्छा माध्यम है। सहकारी समितियों जैसे सामाजिक संगठनों के एक बड़े नेटवर्क की उपस्थिति, पूंजी के निर्माण और उपयोग में सहायक होगी तथा 'जितनी अधिक सामाजिक पूंजी होगी, विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी'।■

राष्ट्रीय संयोजक, पैक्स प्रकोष्ठ
सहकार भारती

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष भूटानी, संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन और नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के वी सहित देश भर के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्षों, अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों ने राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय (एनबीएससी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में की भागीदारी।

'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूर्वोत्तर भारत के मेघालय की राजधानी शिलांग में 'सहकारिता के बीच सहयोग' विषय पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इस दौरान 'दो लाख नए एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स द्वारा तीन अतिरिक्त सेवाएं' शीर्षक से एक कार्यशाला भी आयोजित हुई।

एनसीयूआई के राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने सहकारी विकास रणनीतियों और सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को लेकर सहकारी शिक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सात राज्यों के 31 प्रतिभागियों ने भागीदारी की।

देश में सहकारी कर्मियों के ज्ञान और प्रबंधकीय कौशल को मजबूत करने और सहकारी परिदृश्य की समझ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने उत्तर प्रदेश के आंवला में इफको संयंत्र के अधिकारियों के लिए 'सहकारिता और सहकारी प्रबंधन' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया।

एनसीयूआई के कॉप कनेक्ट डिवीजन ने महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में सहकारिता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 50 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें एनसीयूआई के कार्यकारी निदेशक श्री राजीव शर्मा और उप निदेशक श्री अनंत दुबे एवं अन्य अधिकारियों ने सहकारी मॉडल और अर्थव्यवस्था के बारे में युवाओं की समझ विकसित की।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें किसान सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका पर विस्तृत संवाद हुआ।

सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। देश में 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़कर काम कर रही हैं। हर सेक्टर में ऐसा बदलाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहा है, रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ा रहा है।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (CEAS-LMS) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: राजीव शर्मा

Postal Registration No: DL-SW-01/4214/2023-24
Published on 15.06.2025 RNI No.: DLHIN/25/A0141

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ